



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1944 (श10)

(सं० पटना 644) पटना, बुधवार, 31 अगस्त 2022

सं० 2/आरोप-01-14/2019-सा0प्र0/9530
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

13 जून 2022

श्री अनिल कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 940/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मसौढ़ी के विरुद्ध महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 269/2016-17, 806/2014-15 एवं 244/2008-09 में उठाये गये आपत्तियों का निराकरण नहीं करने तथा विभागीय दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने संबंधी आरोप के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2704 दिनांक 31.05.2019 द्वारा आरोप-पत्र (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराया गया।

नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त आरोप-पत्र एवं संचिका में उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित आरोप-पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों के लिए श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के समीक्षोपरान्त आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8483 दिनांक 18.09.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 988/स्था० दिनांक 02.11.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को आंशिक प्रमाणित एवं शेष आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में उल्लेखित किया गया कि श्री कुमार को तीन माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार (ले०ह०), बिहार, पटना का भेजे जाने का विभागीय निदेश दिया गया। पुनः स्मारित करते हुए इन्हें एक पक्ष के अन्दर महालेखाकार (ले०ह०), बिहार, पटना को भेजे जाने हेतु निदेश दिया गया, परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा उक्त अनुपालन प्रतिवेदन नगर परिषद्, मसौढ़ी में अपने पदस्थापन अवधि दिनांक 12.11.2018 तक नहीं भेजा जा सका। संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष में यह भी उल्लेखित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 12.11.2018 को नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मसौढ़ी का प्रभार अन्य पदाधिकारी को सौंपने के फलस्वरूप अनुपालन प्रतिवेदन को नगर परिषद् बोर्ड के बैठक में अनुमोदित नहीं करा सके, जिसके फलस्वरूप आरोपी पदाधिकारी के द्वारा भी पूर्व में पदस्थापित तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी के तरह उक्त लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार (ले०ह०), बिहार, पटना को नहीं भेजा जा सका।

आंशिक प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा उक्त के आलोक में लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन में मुख्यतया इनके विरुद्ध

गठित आरोप को ही तथ्यहीन, निराधार एवं तकनीकी रूप से गलत होने का उल्लेख किया गया। इनके द्वारा जाँच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया गया।

प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4165 दिनांक 17.03.2022 द्वारा **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18) एवं (ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश पर पुनर्विचार करने हेतु श्री कुमार के पत्रांक-शून्य दिनांक 28.03.2022 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें इनका मुख्य रूप से कहना है कि :-

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 4165 दिनांक 17.03.2022 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित दण्डादेश बिहार सी0सी0ए0 रूल्स, 2005 के नियम-19 के विरुद्ध है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन बिहार सी0सी0ए0 रूल्स, 2005 के नियम-17(23)(1) के अनुसार तैयार नहीं किया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 3643 दिनांक 14.10.2020 द्वारा श्री उमाकान्त पाण्डेय, प्रभारी परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया, किन्तु संचालन पदाधिकारी ने श्री बुद्ध प्रकाश, परियोजना पदाधिकारी-सह-उप निदेशक को अपनी मर्जी से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मानते हुए उनसे इनके बचाव बयान के प्रतिपरीक्षण के संदर्भ में पत्रांक 455 दिनांक 11.06.2021 एवं पत्रांक 563 दिनांक 05.07.2021 द्वारा आरोपवार साक्ष्य की मांग की गई, जो बिल्कुल ही बिहार सी0सी0ए0 रूल्स, 2005 के विरुद्ध है।

विभागीय कार्यवाही में आरोप को प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा किसी भी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया। संचालन पदाधिकारी ने प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की भूमिका निभाते हुए जांच प्रतिवेदन में अपना मतव्य दिया कि आरोप संख्या-01, 02, 04 एवं 06 अंशतः प्रमाणित होता है, जो कि पूरी तरह से गलत है।

संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 1031 दिनांक 25.01.2021 द्वारा दिये गये निदेश का घोर उल्लंघन किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा ससमय आरोप का निष्पादन नहीं किया गया, जो परिपत्र संख्या 2178 दिनांक 28.02.2007 का उल्लंघन है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय जांच से संबंधित दैनिक आदेश फलक उचित तरीके से संघारित नहीं किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय का आरोपों के संबंध में **observation** है कि-**"F.I.R. & complaint petition/charges in departmental proceeding is not a substantive piece of evidence and on the basis of Memo of Charges, charges cannot be proved"** इनके मामले में भी किसी भी आरोप को साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया तथा आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी दस्तावेजों को **Exhibit** नहीं कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के क्रम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(1) में निहित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

इनके स्थानान्तरण के दो माह बाद भी कुल 37 नगर निकायों में अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन लंबित था, किन्तु सिर्फ इनके विरुद्ध ही कार्रवाई की गई। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 एवं 16 का उल्लंघन है।

कार्य के आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि-

"However lack of efficiency and failure to attain the highest standard of administrative ability while holding high post would not by themselves constitute misconduct. There may be negligence in performance of duty and a lapse in performance of duty or error of judgment in evaluating the developing situation may be negligence in discharge of duty, but would not constitute misconduct unless the consequences directly attributable to negligence would be such as to be irreparable or the resultant damage would be so heavy that the degree of culpability would be very high. An error can be indicative of negligence and the degree of culpability may indicate the grossness of the negligence. Carelessness can often be productive of more harm than deliberate wickedness or malevolence. But in any case, failure to attain the highest standard of efficiency in performance of duty permitting an inference of negligence would not constitute misconduct nor for the purpose of Rule-3 of the conduct Rules as would indicate lack of devotion to duty."

जैसे **criminal case** में आरोप को प्रमाणित करने के लिए गवाह को प्रस्तुत कर आरोप को प्रमाणित किया जाता है, अभियुक्त को **Cross Examination** करने के मौका देकर, ठीक उसी प्रकार **civil cases** या विभागीय कार्यवाही में **Author of the documents** की गवाही करायी जाएगी तथा **delinquent employee** को **cross examination** का मौका देकर, परन्तु ऐसा नहीं किया गया जो कि स्पष्टतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय का उल्लंघन है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय **Reported** है। **AIR S.C. 1964 page 246 H.C. Goel Versus The Union of India.**

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में उनसे प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। उनके द्वारा अपने अभिकथन में मुख्यतः संचालित विभागीय कार्यवाही को ही तथ्यहीन, निराधार, तकनीकी रूप से गलत एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों के विपरीत होने का उल्लेख किया गया है, जबकि नियमानुसार श्री कुमार द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में ही संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए था।

महालेखाकार द्वारा पत्रांक 14587 दिनांक 20.09.2016 के माध्यम से नगर परिषद् मसौढ़ी के वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन की माँग पत्र प्राप्ति के तीन माह के अंदर की गई थी। आरोपी पदाधिकारी का पदस्थापन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, मसौढ़ी के पद पर दिनांक 12.07.2017 से 25.10.2018 तक रहे हैं। महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदन ससमय नहीं भेजे जाने के फलस्वरूप नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लगातार स्मारित किया जाता रहा। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 1950 दिनांक 30.08.2018 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन ससमय नहीं भेजे जाने का कारण स्पष्ट करते हुए दिनांक 15.09.2018 तक साक्ष्य सहित प्रतिवेदन महालेखाकार को भेजे जाने हेतु निदेश दिया गया। उक्त पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया कि प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने पर श्री कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। श्री कुमार के द्वारा निदेश एवं अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दिये जाने के बावजूद भी महालेखाकार को वांछित प्रतिवेदन नहीं भेजा जा सका। स्पष्टतया श्री कुमार का कार्यपालक पदाधिकारी के पदस्थापन अवधि एक वर्ष तीन माह तक अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को भेजने की कार्रवाई नहीं की गई। श्री कुमार का यह आचरण एक वरीय पदाधिकारी के कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4165 दिनांक 17.03.2022 द्वारा संसूचित एवं अधिरोपित दंड (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18) एवं (ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक को पूर्ववत् बरकरार रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अनिल कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 940/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मसौढ़ी के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4165 दिनांक 17.03.2022 द्वारा संसूचित एवं अधिरोपित दंड (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18) एवं (ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 644-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>